

पढ़ने व खेलने की उम्र में लकड़ी ढोने को मजबूर आदिवासियों के बच्चे

लकड़ी के बोझ तले नौनिहालों का दबा बचपन, बजट में बट्टा लगाने का काम करते हैं अधिकारी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 14 अप्रैल। प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें अनेकों योजनाओं के माध्यम से पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है मगर विभागों में दशकों से जमे बैठे बैठे अधिकारी इन जनहित की योजनाओं को कागजों तक सीमित रखते हुए शासन द्वारा प्राप्त होने वाले बजट में बट्टा लगाने का काम करते आ रहे हैं, जिससे जिले के मजदूरों किसानों की हालत सुधारने का नाम नहीं ले रही है।

अनेकों शिकायतों के बावजूद भी इन पर कोई कार्यवाही नहीं देखी जाती ग्रामीण इलाकों के पीडित



लोगों द्वारा सोएम हेलपलाइन पर की जाने वाली शिकायत शिकायतकर्ताओं के लिए मुसीबत साबित हो रही है। क्योंकि कार्रवाई की बजाय कायदाओं को ही प्रताड़ित किया जाने लगता है वहीं

जनसुनवाई में दिए जाने वाले आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को आदेश तो जारी कर दिया जाता है मगर वह केवल कागजों तक ही सीमित रहता है जमीनी हकीकत पर अगर निगाह डाली जाए तो जिले के

किसानों मजदूरों और आदिवासियों की हालत पहले की तरह की बदहाल है। इन पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है पीएम आवास से लेकर कृषि एवं मजदूर उत्थान की योजनाएं अभी भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रही हैं पत्थर खदानों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चे और मजदूर गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही इस कदर हावी है कि शिक्षा और मध्याह्न भोजन भी ठीक तरह से बच्चों को नसीब नहीं हो रहा स्वास्थ्य की बात करें तो जिला चिकित्सालय के नाम पर गरीब लोगों को सही इलाज तक नहीं मिलता।

जिले से पलायन कर गए हजारों मजदूर

गरीबों के चलते हजारों लोग पन्ना जिले से महानगरों की ओर पलायन कर चुके हैं जो महानगरों में रहकर भी दैनिकी जिंदगी जीने को मजबूर हैं यहां उन्हें पैसा तो मिल जाता है मगर बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं गर्भवती महिलाएं बड़े बुजुर्ग एवं बच्चों को भी काम करना पड़ता है स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती इनके अलावा आदिवासी मजदूरों के बच्चे खेलने कुदने व पढ़ने लिखने की उम्र या तो लकड़ी का भारी भरकम बोझ सर पर लेकर शहर में जाकर बेचने को मजबूर हैं या फिर नाजुक हाथों में हथौड़ी और पत्थर लेकर गिट्टी फेंडना पड़ता है जिससे उन्हें दो वक्त की रोटी नसीब हो पाती है इसके अलावा आदिवासियों के अधिकतर बच्चे आलीशान हवेलियों में बाल बंधुआ मजदूरी के नाम पर कैद हैं, जहां उन्हें या तो जागीरदारों के यहां भैस चराने का काम करना पड़ता है या फिर बर्तन धोने से लेकर सफाई के काम भी करने पड़ते हैं और कुछ बच्चे अमीरों की खेलों की रखवाली करते हैं। उन जमींदारों में कई प्रतिष्ठित नेता भी शामिल हैं जिनका वेहरा समाज में काफी स्वच्छ छवि वाला माना जाता है मगर अंदरूनी हकीकत काफी चोका देने वाली रहती है।



समितियों में सदस्यता अभियान का अंबेडकर जयंती पर हुआ शुभारंभ

नवभारत न्यूज

पन्ना, 14 अप्रैल। मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित कृषक कल्याण वर्ष-2026 अंतर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित पगरा में शासन के निर्देशानुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शुभ जयंती के अवसर पर समितियों में नवीन कृषकों को सदस्य बनाए जाने के अभियान का शुभारंभ किया गया।

मुख्यालय से उपस्थित वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अमित श्रीवास्तव प्रशासक विष्णु दीक्षित एवं शाखा अमानांगज के शाखा प्रबंधक द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती का पूजन कर दीप प्रज्वलित कर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर पुष्प माला अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कृषकों को समिति की योजनाओं की जानकारी देते हुए वरिष्ठ शाखा प्रबंधक एवं फ़ैल्ड प्रभारी अमित श्रीवास्तव द्वारा संस्था के गौर सदस्यों को सदस्य बनाने हेतु

संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी गई संस्था द्वारा कृषकों को मध्य प्रदेश शासन की योजना अनुसार 0 प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण एवं कृषि आदान साथ ही कृषि से संबंधित अन्य ऋणों की जानकारी दी गई इसी प्रकार प्रशासक विष्णु दीक्षित द्वारा सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए शासन की योजनाओं की जानकारी शाखा प्रबंधक द्वारा संस्था के गौर सदस्यों को सदस्य बनाए जाने के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम अंतर्गत ही लगभग 10 से 15 नवीन सदस्य बनाए गए यह कार्यक्रम प्रदेश भर में आज से प्रारंभ हो गया है तथा उसी क्रम में जिले की सभी समितियों में आज से सदस्यता अभियान जारी है जिसका शुभारंभ अमानांगज ब्रांच अंतर्गत समिति पगरा से किया गया कार्यक्रम में संस्था का क्षेत्र के कृषक एवं वरिष्ठ कृषक राम केश पांडे सुरेंद्र पांडे एवं संस्था के कर्मचारी समिति प्रबंधक रिश्वत ठाकरे सहायक समिति प्रबंधक राजेश उपाध्याय एवं सभी विक्रेता उपस्थित रहे।

पशु का शिकार करने के बाद से बाघ की सर्चिंग जारी

ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील

नवभारत न्यूज

पन्ना 14 अप्रैल। गत तीन दिन पूर्व जसवंतपुरा में बाघ द्वारा एक पड़दा का शिकार किये जाने की सूचना पन्ना टाइगर रिजर्व के अमले को मिली थी, सूचना पाते ही अमला हाथियों सहित सर्चिंग में जुट गया था लेकिन अभी तक बाघ नहीं दिख सका। हासिल जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल को ग्राम वासियों द्वारा बीट गार्ड जसवंतपुरा को सूचित किया गया कि ग्राम क्षेत्र के आस



पास एक बाघ ने पड़े का शिकार किया है। इसके पश्चात वन अमले

द्वारा मौके पर पहुंचकर तलाशी शुरू की। प्रत्यक्ष बाघ को देखने के

बाद वन अमले ने ग्रामवासियों को बाघ से सुरक्षित दूरी पर रखने की अपील की गई। बाघ की निरंतर निगरानी की गई। इसके पश्चात गत दिवस बाघ को वन क्षेत्र की ओर वापस भेजने हेतु हाथियों को बुलवाकर क्षेत्र की सर्चिंग की गई। बाघ के चर्चों झाड़ियों में होने के कारण बाघ को वन क्षेत्र की ओर वापस नहीं भेजा जा सका। वन अमले द्वारा बाघ की रात भर निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। आज पुनः प्रातः काल से सर्चिंग

प्रारंभ की गई। सम्पूर्ण क्षेत्र की तीन हाथियों से सर्चिंग कराने के पश्चात बाघ नहीं मिला। मौके पर बाघ के वन क्षेत्र की ओर जाने के पदचिह्न दिखाई दिए। मृत पड़े के पशुमालिक की ओर से मुआवजे का आवेदन प्राप्त किया गया है एवं त्वरित मुआवजा राशि प्रदाय किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। ग्राम वासियों को सुरक्षित रहने एवं बाघ विचरण क्षेत्र में न जाने की समझाइश दी गई। स्टाफ़द्वारा क्षेत्र की निगरानी की जा रही है।

मीडिएशन सेंटर पर्वट एवं अजयगढ़ का ई-लोकार्पण 17 को

पन्ना 14 अप्रैल। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति पर्वट एवं अजयगढ़ में नवनियुक्त मीडिएशन सेंटर का ई-लोकार्पण शुक्रवार, 17 अप्रैल को शाम 5 बजे होगा।

उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक द्वारा मीडिएशन सेंटर का ई-उद्घाटन किया जाएगा।

उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक द्वारा मीडिएशन सेंटर का ई-उद्घाटन किया जाएगा।



शहीद वनरक्षक हरिकेश गुर्जर की स्मृति में हरिकेश वन की स्थापना

नवभारत न्यूज

पन्ना 14 अप्रैल। दक्षिण पन्ना वनमंडल के रैपुरा वन परिक्षेत्र की भगनरवा बीट में शहीद वनरक्षक स्वर्गीय हरिकेश गुर्जर की स्मृति में एक पौधरोपण स्थल का नामकरण हरिकेश वन किया गया। इस अवसर पर विधिवत पूजा-अर्चना के उपरांत उपस्थित अधिकारियों, वनकर्मियों तथा ग्राम वन समिति सुरा के सदस्यों ने स्वर्गीय हरिकेश गुर्जर को भावभंगी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान स्मृति पट्टा का अनावरण भी किया गया। ग्राम स्तरीय सहभागिता के साथ यह सादगीपूर्ण किंतु अत्यंत भावपूर्ण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेश सिंह यादव, मुख्य वन संरक्षक, खरपुर वन वृत्त रहे। कार्यक्रम में अक्षत जैन, भा.व.से., पर्वट उपवनमण्डल अधिकारी, पंकज चौधरी, भा.व.से. प्रशिक्षु, विवेक जैन, वन परिक्षेत्र अधिकारी रैपुरा; अशोक पांडे, डिप्टी रेंजर; सतीश द्विवेदी, वनरक्षक/बीट गार्ड; स्थानीय वन अमला तथा ग्राम वन समिति सुरा के ग्रामीण सदस्य उपस्थित रहे।

समारोह में शहीद वनरक्षक के योगदान को स्मरण करते हुए यह संकल्प व्यक्त किया गया कि वन एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति उनकी निष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। उल्लेखनीय है कि वनरक्षक हरिकेश गुर्जर की हाल ही में मुरैना जिले में अवैध रेत खनन के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान कर्तव्य पालन करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर शहादत हुई थी। वे कई वर्षों तक पन्ना टाइगर रिजर्व में सेवानिवृत्त के बाद वर्ष 2025 में स्वयं के अनुरोध पर मुरैना स्थानांतरित हुए थे। उनका यह सर्वोच्च बलिदान वन पर्यटकों को वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण का प्रतीक है। आगामी मानसून 2026 में यहाँ 40,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। हरिकेश वन केवल एक पौधरोपण स्थल नहीं, बल्कि कर्तव्य, साहस और बलिदान की जीवंत स्मृति के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी भावना से दक्षिण पन्ना वनमंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शहीद के परिवार के प्रति कृतज्ञता एवं संवेदना व्यक्त करते हुए ₹25,000 की सहयोग राशि भी प्रदान की है।

हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला, जनता को सर्वाधिक परेशानी राजस्व अमले से

नवभारत न्यूज
पन्ना 14 अप्रैल। जिले में राजस्व की चोरी शासकीय

नुमाईदें व निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की साठ गांठ से खुलेआम लूट तंत्र चल रहा

राजस्व कार्यालय में भी मची है लूटमार
जिला कलेक्टर कार्यालय के समीप राजस्व कार्यालय में राजस्व की चोरी के लिये भी स्टाप ड्यूटी व पंजीयन फीस के अलावा सुविधा शुल्क दलास से लेकर राजस्व कार्यालय में पंजीयक व उप पंजीयक से बाबुओं तक को चढौतरी देनी पड़ती है। तब जाकर राजस्व हो पाती है। ऑनलाइन राजस्व होने के बाद भी पटवारी द्वारा बनाया पर्चा व अन्य दस्तावेजों से नूट निकालकर राजस्व कार्यालय में लेन देन की सेंटिंग बना ली जाती है। इसी तरह स्टा म बंडरों के द्वारा स्टा म बंडरों के द्वारा स्टा म की मूल कीमत से बढ़ाकर विक्रय किया जाता है और राजस्व साहब को शिकायत करने पर स्टा म बंडरों का सपोर्ट किया जाता है। जिससे स्पष्ट है की राजस्व साहब को भी बंडरों द्वारा कुछ मुद्राएं चढौतरी में दी जाती हैं।

राजस्व की चोरी के अलावा सभी शासकीय विभागों में रिश्वत लिये बगैर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। जहां तक की रिश्वत के मामले में न्याय विभाग भी अछूता नहीं है। राजस्व विभाग में भी भूमि क्रय और विक्रय के लिये पर्चा बनवाने के लिये 5000 रुपये से लेकर 10000 हजार रुपये लिये जाते हैं तब जाकर एक पत्रे का पर्चा बनाया जाता है। इसी तरह नामांतरण के बाद ऑनलाइन अपडेशन व षष्ठा पुस्तिका बनाने व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के लिये भी हजारों रूपये की रिश्वत ली

जाती है। इसी तरह सीमांकन के लिये भी कृषक से मोटी रकम ली जाती है। अवैध कब्जे की शिकायत पटवारी से लेकर तहसीलदार को सूचना देने पर अवैध कब्जा धारियों से ले देकर अभयदान दे दिया जाता है। सबके सब चोर और रिश्वतखोर हैं। जिन पर नकेल कसने वाले भी चोर हैं। न्याय विभाग में गरीब से लेकर रईस लोगों से न्याय विभाग में बैठे बाबुओं के द्वारा पेशी बढ़ाने व जमानत कराने के नाम से या पट्टा कटवाने के नाम से भी बाबुओं से लेकर चपरासी तक को रूपये देना पड़ता है तब जाकर न्याय

विभाग से काम होता है। इन बाबुओं के द्वारा न्यायालय से प्रति दिन हजारों रूपये रिश्वत से कमाकर अपने बीबी बच्चों की

रिश्वत की रोटी खिलाते हैं और अपनी तलाखवा से एक रूपये खर्च नहीं करते पूरा काम रिश्वत की राशि से चलता है।

भ्रष्टाचारी छान रहे मलाई, बेगुनाह हैं जेल में
लडाई इमडों से लेकर अन्य मामले में रईस लोगों से पुलिस थाना में ले देकर छोड़ दिया जाता है और गरीबों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाता है। पुलिस विभाग में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। पुलिस थाना आती है और रईस लोगों से रिश्वत लेकर गरीब के ऊपर झूठा मामला पंजीबद्ध कर दिया जाता है। भले ही गरीब अपराध ना किया हो। इस तरह सारे विभाग में भ्रष्टाचार का तानाबाना फैला हुआ है। जिसके जमनेदार आप और हम हैं। सब कुछ होता है ही सहन कर रहे हैं जिसका फायदा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों व आलाधिकारी से सब फायदा उठा रहे हैं।

नारी शक्ति वंदन सम्मेलन आयोजित

प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया

नवभारत न्यूज
पन्ना, 14 अप्रैल। शासन के निर्देशानुसार सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया।

जिला स्तरीय कार्यक्रम में कलेक्टर ऊषा परमार सहित सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे। इसके उपरांत जिला कलेक्टर ने आगामी 25 अप्रैल तक आयोजित नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा के तहत संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक समन्वय के साथ जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित कर सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों के

आयोजन के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में जिले की सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी नारी शक्ति वंदन सम्मेलन आयोजित किया गया। उपस्थितजनों ने विभिन्न स्थानों पर प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। जिला स्तर पर एनआईसी कक्ष सहित जनपद पंचायत, नगर पालिका एवं नगर परिषद,

हीरे की वैध एवं अवैध खदानों में पसीना बहा रहे मजदूर

नवभारत न्यूज
पन्ना, 14 अप्रैल। पत्थर की तरह हीरा की भी वैध से लगभग दस गुना अधिक अवैध हीरा की खदानें चल रही हैं। हीरा खनन माफिया वर्षों से इस कार्य को अजमा देते आ रहे हैं। जिसमें प्रशासनिक एवं राजनैतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त है। वैध खदानें केवल नये लोग चलाते हैं उन्हीं का हीरा कार्यालय में जमा होता है शेष सभी कालाबाजारी की भेंट चढ़ जाते हैं।

हालांकि जिले की अधिकांश वैध हीरा खदानें बंद होने से लोग निजी भूमि में पट्टा लेकर या वन भूमि में चोरी-छिपे खदान संचालित कर रहे



हैं। कृष्णा कल्याणपुर, जनकपुर, पटी बजरिया, गांधी ग्राम, रक्सवा, रहुनिया, बडगडी, क्षेत्र में सैंकड़ों

अवैध हीरा खदानें संचालित हैं, जहां कुछ लोगों को तो कम समय में हीरा मिल जाता है पर कुछ लंबे समय तक पैसा और पसीना बहाते रहते हैं।

कठिन परिश्रम व जोखिम से मिलता है हीरा

पन्ना की धरती में बेसकीमती हीरे यूं ही नहीं मिलते इसके लिये कठिन परिश्रम और जोखिम उठाना पड़ता है, घने जंगलों से लगी खदानों में अनिर्गत लोग खदान खोद रहे हैं। आस-पास के लोग तो दिन भर काम कर शाम को अपने घर चले जाते हैं, पर बाहरी लोग खदानों में घस-फूस की झोपड़ी बना कर रहते हैं, जहां एक ओर जंगली जानवरों का खतरा और दूसरी ओर कड़ाके की ठंड में रात बिताते हैं। तब कहीं हीरा नसीब होता है।

वैध खदानों के नाम पर जमा हो रहे अवैध खदानों के हीरे:-स्थानीय खदान संचालक के अनुसार जिले की अधिकांश वैध खदानें बंद है लोग मजबूरी में अवैध खदान खोदने को मजबूर हैं। क्योंकि चंद चालू वैध खदानें सैंकड़ों बार खुद चुकी हैं, इसलिये इन खदानों में हीरा मिलना मुश्किल होता है।

बिना मापदंड पूरा किए चल रहे निजी विद्यालय, एक ही भवन में चल रहे कई स्कूल एवं कॉलेज

भवन एक चल रहे कई शैक्षणिक संस्थान, कागजों में कुछ और, निजी विद्यालय भवनों का हो रहा मैरिज गार्डन के रूप में उपयोग

नवभारत न्यूज

पन्ना, 14 अप्रैल। पन्ना जिला मुख्यालय सहित समूचे जिले में लगभग 80 प्रतिशत निजी

विद्यालय बिना निर्धारित मापदंडों को पूरा किये चल रहे हैं। यही नहीं एक ही भवन में कई विद्यालयों एवं कॉलेजों का

संचालन हो रहा है और कागजी कार्यवाही में प्रथक प्रथक दिखाया गया है। साथ ही पन्ना में आवासीय विद्यालयों को नहीं दी गई है कि लेकिन इसके बावजूद बिना मापदंडों को पूरा किये हो रहा है। यही नहीं अब तो निजी विद्यालयों ने अपने विद्यालयों को मैरिज गार्डन में भी उपयोग करना शुरू कर दिया है। अच्छी शिक्षा के नाम पर अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलने वाले निजी स्कूल सुविधाओं के मामले में शून्य हैं। इन स्कूलों के पास न तो पर्याप्त भवन हैं और न ही खेल मैदान।

चंद कमरों में संचालित ये स्कूल मान्यता के नियमों पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं। बावजूद शिक्षा महकमा नियमों को अनदेखा कर संचालित होने वाले निजी विद्यालयों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। शहरी क्षेत्र में लगभग तीन दर्जन से अधिक निजी स्कूल संचालित हैं। इनमें से कुछ स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश मान्यता के मापदंडों पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ शैक्षणिक माहौल प्रदान करने का दावा करने वाले इन निजी विद्यालयों के पास न तो पर्याप्त भवन हैं और न ही खेल मैदान। शहरी क्षेत्र में तो लगभग

40 से अधिक निजी स्कूल संचालित हैं, जिनके पास प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल की मान्यता है, लेकिन स्कूल भव के नाम पर केवल दो से तीन कमरों हैं, जिन्हें भेड बकरियों की तरह

बच्चों को प्रति वर्ष बैठकर स्कूलों का संचालन होता चला आ रहा है। जिला स्तर पर इन स्कूलों को मान्यता किस आधार पर प्रदान कर दी जाती है, इस पर सवालिया निशान उठता चला आ रहा है।

कागजों में कॉलम, हकीकत में शून्य

निजी विद्यालयों को नवीन मान्यता प्राप्त अथवा नवीनीकरण के समय शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला एक फर्म भरना होता है, जिसमें विद्यालय की संपूर्ण जानकारी फर्मट होता है। इसमें विद्यालय भवन के साथ संसाधन आदि के बारे में पूछा जाता है निजी स्कूल संचालक मान्यता प्राप्त के समय इन कॉलम को तो कूटरचित ढंग से पूरा कर देते हैं। हकीकत में संसाधन उनके पास होते नहीं है और उनके इस घालमेल अप्सर करते हैं। जिन्हें इन विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यही अधिकारी इन स्कूलों के संचालकों को बचा लेते हैं।

आज से वन विभाग को कब्जा सौंपने की शुरु होगी कार्रवाई

नवभारत न्यूज
पन्ना, 14 अप्रैल। केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के लिए ग्राम कटहरी बिलहटा, कोनी, मझौली एवं डोड़ी में अर्जन की कार्यवाही उपरांत म्हाअवाजा राशि भुगतान कार्य पूर्ण हो चुका है।

अब बुधवार, 15 अप्रैल को सुबह 9 बजे से इन ग्रामों की भूमि, परिसम्पत्तियों, मकान एवं भवन इत्यादि को हटाया जाकर वन विभाग पन्ना टाइगर रिजर्व को कब्जा सौंपने की कार्यवाही आरंभ की जाएगी। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना कार्यालय द्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से जनसामान्य

को सूचित किया गया है। एसडीएम संजय कुमार नागवंशी ने उक्त ग्रामों में संबोधितजनों को अधिग्रहण पश्चात संपत्ति रिक्त कर अपना कब्जा हटाने के संबंध में सूचित किया है अन्यथा किसी भी प्रकार की हानि के लिए संबंधित स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा शासकीय तौर से मौका स्थल से इन्हें हटाने की कार्यवाही की जाएगी। हल्का पटवारी कटहरी बिलहटा को ग्राम कोटवार के माध्यम से मुनादी करने तथा प्रत्येक ग्राम में आम चौराहा एवं स्थान पर सूचना की प्रति चप्पा कर तामोली भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।